विश्व राजनीति में चीन की भूमिका : वर्तमान संदर्भ में

डॉ. बीना महलावत [1]

[1] **पीडी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान.**

ABSTRACT:

कहते है इतिहास अपने आप को दोहराता है, चाहे कितना भी समय लगे। यही अभी चीन के साथ हो रहा है। एक समय में विश्व के मामलों और व्यापार से दूर रहने वाले चीन को आज फिर से मजबूरन उसी एकांतवास में जाना पड रहा है। यानि 20 वी शताब्दी में विकास के नए आयाम को छू कर 'विश्व का फैक्ट्री बनने वाले चीन को 21वीं शताब्दी के दूसरे ही दशक में फिर से विश्व के व्यापार से दूर होना पड रहा है। चीन के ही वुहान से फैलने वाले कोरोना ने आज यह हालात पैदा कर दिया है कि कोई भी देश चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और न ही चीन से व्यापार करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। वर्तमान आर्थिक स्थिति ने सभी बडे आर्थिक देशों के साथ तनावों को जन्म दिया है और इसी तनाव के कारण सभी देश चीन को ग्लोबल सप्लाइ चेन से बाहर करने का प्लान भी बना चुके है। 30 अप्रैल 2020 को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है. ताकि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोम्पियो ने कहा 'हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैश्विक सप्लाई चेन दुरुस्त हो और हम सभी देश अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सके, ताकि किसी भी देश के सामने दोबारा कभी ऐसी स्थिति पेश न हो। इसका एक उदाहरण हमें भारत में देखने को मिला जब भारत ने कोविड के मरीजों के उपचार के संबंध में जरूरी दवाइयों के एक्सपोर्ट पर से बैन हटाकर उन्हें दुनियाभर में एक्सपोर्ट किया।"

KEYWORDS:

-

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
26th April 2025	29th April 2025

प्रस्तावना

चीन के एक दलीय शासन और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ कम्युनिस्ट पार्टी 'सीपीसी' के दबदबे ने इस देश के राजनीतिक तंत्र के संदर्भ में हमेशा एक रहस्यमयी वातावरण बनाए रखा है। फरवरी 1972 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा हुई तब से पश्चिमी मीडिया सीपीसी के समीकरणों को समझने और सामने लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तब पश्चिम को दो दशक के बाद पहली बार चीन के राजनीतिक ढांचे में झांकने का मौका मिला था। चीन की राजनीति ने शायद ही कभी दुनिया को अर्थपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई हो। इस लिहाज से सीपीसी की चागकिंग कमेटी के पूर्व सचिव बो जिलाई से जुड़ा हाल का घटनाक्रम बहुत उल्लेखनीय नजर आता है। चागकिंग दक्षिण-पश्चिम चीन का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो 1997 में शिचुआन प्रात से अलग हुआ। यह शहर उन चार महानगरपालिकाओं में शामिल है जो सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा शासित है। अन्य तीन महानगरपालिकाएं है बीजिंग, शघाई और तियानजिन। चोगकिग के निर्विवाद राजनीतिक नेता के रूप में बो जिलाई का शहर में कार्यकाल बहुत अधिक सफल रहा।

बो के कार्यकाल की राजनीतिक विशिष्टता थी उनके द्वारा माओ और लाल क्रांति की यादे ताजा करने के लिए किए गए प्रयास। इस तरह से वह एक हद तक चीन में पुराने कट्टर वामपंथ की विचारधारा को फिर से स्थापित करते नजर आए। वो 2007 तक चीन की सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने में बो को मिली सफलता इससे प्रमाणित होती है कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2010 में विश्व के सबसे अधिक प्रभावशाली लोगो में शामिल किया। यह चीन के लिए एक विलक्षण घटना थी, क्योकि वहां शायद ही राजनेताओं को अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता मिलती है। उन्हें इस वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के नौ सदस्यीय पोलिट ब्यूरो का स्थायी सदस्य भी बनना था. लेकिन पिछले महीने उनके राजनीतिक भाग्य ने करवट ली और उन्हें चागकिंग कमेटी के सचिव पद के साथ-साथ सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो सचिव के रूप में कार्यवाहक सदस्य, से भी बर्खास्त कर दिया गया। बो जिलाई के कैरियर में चौकाने वाला यह परिवर्तन चांगकिंग के पुलिस प्रमुख वाग लिजुन के आरोपो के बाद आया। वाग ने यह गंभीर आरोप लगाया कि बो भ्रष्ट है और आपराधिक गतिविधियों में सलग्न है। इसके बाद वो की पत्नी और एक मशहूर वकील गू केलाई पर 2011 के अंत में एक ब्रिटिश व्यवसायी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। इस तरह केवल बो ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए हालात बेहद कठिन हो गए। चौथी पीढी के बाद से चीन धीरे-धीरे सामूहिक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है. जबकि पहले व्यक्तिगत और केंदीय शासन ही चीन की पहचान रहा है। पोलिट ब्यूरो के सबसे प्रमुख सदस्य अर्थात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच अब शक्तियों का संतुलित बटवारा कर दिया गया है. जबकि अन्य सदस्यों के पास अपेक्षाकृत कम शक्ति है। सत्ता का दायरा बढ़ जाने के कारण ही सत्ता के दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं. मुख्यत आर्थिक नीतियों की भूमिका के कारण सीपीसी में मतभेद भी बढ़े हैं।[1]

बीते 40 वर्षो में चीन ने व्यापारिक रास्ते खोलने और निवेश लाने के लिए अपने बाजार की व्यवस्था में कई ऐसे सुधार किए जो ऐतिहासिक है। इस तरह चीन अपने करोडों लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर खीच लाया। चीन में 1950 का दशक 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी का साक्षी बना। माओ त्सेतुंग ने आनन -फानन में चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण की कोशिश की लेकिन यह प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। हालात तब और खराब हो गए जब 1959-1961 के बीच अकाल ने 10-40 लाख लोगों की जानें ले ली। इसे चीन की 'महान सर्वहारा क्रांति' के नाम से जाना जाता है। यह माओ त्सेतुंग का चलाया एक सामाजिक -राजनीतिक आदोलन था और इसका मकसद था कम्युनिस्ट पार्टी को उसके प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा दिलाना मगर इसका अंत चीन के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करके हुआ। 1990 तक चीन की आर्थिक विकास दर तेजी से बढ़ने लगी और साल 2001 में ये विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा कदम था। इसके बाद चीन के लिए दूसरे देशों से व्यापार करना आसान हो गया क्योकि व्यापार शुल्क कम हो गए। इस तरह देखते ही देखते चीनी सामान दुनि या के कोने-कोने में पहुंच गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार साल 1978 में चीन का निर्यात सिर्फ 10 बिलियन डॉलर था। 1985 में ये 35 बिलियन हुआ और अगले दो दशको के भीतर यह 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसी के साथ चीन व्यापार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। विश्व बैंक का कहना है कि चीन में 85 करोड से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है वर्ष 2020 तक चीन से गरीबी पूरी तरह मिट जाएगी। इतना ही नहीं ,

चीन में गरीबी घटने के साथ -साथ यहा शिक्षा के स्तर में सुधार भी हुआ। आंकड़े बताते है कि साल 2030 तक चीन के 27 प्रतिशत कामगर यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा वाले होंगे। ये लगभग वैसा ही होगा जैसा आज जर्मनी में है।

डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के आआंकड़ों के अनुसार चीन में औसत वार्षिक आय लगभग 10 हजार डॉलर है जबकि अमरीका में वार्षिक आय 62 हजार डॉलर है। यानी यहां भी अच्छा-खासा फर्क है। अब चीन तेज आर्थिक विकास दर से धीमी आर्थिक विकास के समय में जा पहुंचा है। पिछले कुछ वर्षों में इसने निर्यात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है और उपभोक्ता आधारित प्रगति के रास्ते पर बढ़ने का प्रयास किया है। पिछले कु छ वक्त में चीनी उत्पादों की मांग में अपेक्षाकृत कमी आई है और अमेरिका से लबे समय से चले आ रहे ट्रेड वॉर ने इसके सामने नई चुनौतियां खड़ी की है। डॉक्टर डेविड मेन कहते है . इस गति के साथ भी चीन वैश्विक आर्थिक विकास का 35 फीसदी हिस्सा है जो किसी देश के तौर पर सब से बड़ा अकेला कॉन्ट्रिब्यूटर है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चीन की आर्थिक तरक्की अमरीका की आर्थिक तरक्की के मुकाबले तीन गुना जयादा महत्वपूर्ण है। चीन वैश्विक आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते भी तैयार कर रहा है। चीन की अगली तैयारी श्वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिवश् परियोजना में उसके भारी निवेश के रूप में देखी जा सकती है। कथित नए सिल्क रूट के जरिए चीन दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के 25 फीसदी जीडीपी को साधने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ वो व्यापार और निवेश के रास्तों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है।[2]

चीन ने पूरी दुनिया को मौत के मुँह में झोंक दिया

चीन ने पिछले दशक से जैविक युद्ध की तैयारिया शुरू कर दी थी और अपनी सेना में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जैव प्रौद्योगिकी का भी समावेश किया। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लोगों को पश्चिम में बढ़ी संख्या में भेजा ताकि वह आधुनिक तकनीक से वाकिफ हो सके। चीन के दो प्रांतों से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरे विश्व के सभी छोटे -बड़े देशों में कोहराम मचा चुका है लेकिन वुहान में सबसे ज्यादा कहर बरसाने याला यह वायरस चीन के अन्य शहरों तक नहीं पहुँचा जोकि अपने आप में चौकाने वाली बात है। सवाल उठता है कि 185 देशों के विभिन्न शहरों में कहर बरपाने वाला यह वायरस चीन के एक ही शहर में क्यों विकराल रूप दिखा पाया? यह वाकई चौकाता है कि वुहान से 1522 किलोमीटर दूर बीजिंग और वुहान से 840 किलोमीटर दूर शंघाई में जो कोरोना वायरस नहीं पहुंचा वह वुहान से 12 हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर न्यूयॉर्क पहुँच गया और वहां सर्वाधिक तबाही जैसे हालात पैदा कर दिये। आज पूरी दुनिया की स्थिति यह है कि चीन से दोगुनी या तीन गुनी मौते इस वायरस के चलते अलग-अलग देशो में हो चुकी है। विश्व अर्थव्यवस्था तबाही के कगार प र पहुँच गयी है तो चीन के उद्योगों में बहार आ गयी है। वहां पर्यटन के सभी केंद्र जिनमें द ग्रेट वाल ऑफ चाइना भी है, खुल गये है। सभी रेस्तरा खुले हैं. कार्यालय खुल गये हैं। एक ओर पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है तो दूसरी ओर चीन में आज स्थिति यह हो गयी है कि चीन दुनिया के विभिन्न देशों को मास्क, हैंड सेनेटाइजर और यहाँ तक कि वेंटीलेटर भी बनाकर भेज रहा है। पूरी दुनिया का उद्योग जगत आईसीयू में है लेकिन चीन के शेयर बाजार छलाँगे मार रहे है। दुनिया के समृद्ध देशों में शुमार इटली में तो स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि लोगों की हालत इतनी खराब हो गयी है कि वह खाने-पीने का सामान नहीं खरीद पा रहे है इसलिए सुपर मार्केट में लूटपाट कर रहे है।[3]

आपकी आखे पूरी तरह खुल सकें इसलिए आपको लिये चलते है चीन में दो दशक पहले आई एक किताब दिखाने। फरवरी 1999 में चीनी सेना के दो जनरलों क्यू लियांग और वांग शियागसुई ने एक पुस्तक लिखी थी अनरेस्ट्रिक्टेड वारफेयर। इसमें यह कहा गया था कि अमेरिका से सैन्य शक्ति के मामले में चीन नहीं निबट सकता इसलिए दूसरा रास्ता चुना जाना चाहिए। यह दूसरा रास्ता था रसायनिक हथियारों का। शायद इसी पुस्तक के निर्देशों का पालन करते ही चीन ने पिछले दशक से जैविक युद्ध की तैयारिया शुरू कर दी थी और अपनी सेना में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जैव प्रौद्योगिकी का भी समावेश किया। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लोगो को पश्चिम में बढी सख्या में भेजा ताकि यह आधुनिक तकनीक से वाकिफ हो सके वहीं दूसरी ओर चीन ने अपने देश में दुनिया की बड़ी आईटी कपनियों को घुसने ही नहीं दिया। पिछले कुछ वर्षों में यह बात समय-समय पर सामने आती रही है कि चीन तरह-तरह के वायरसों का निर्माण कर रहा है। कोरोना वायरस के बारे में भी ऐसी ही खबर आई थी और जिन चीनी डॉक्टर ने इसका खुलासा किया था. पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जनवरी में उन्हें खुद ही इस वायरस से पीडित बताकर मृत बता दिया गया था।[4]

चीन को तो विवश होकर यह कहना पड़ा है कि वह अगले दो वर्ष तक इस महामारी से निपटने में विकासशील देशों को दो अरब डॉलर की सहायता देगा। यह घटनाक्रम एक ऐसे समय में हुआ है जब भारत विश्व स्वास्थ्य महासभा के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनने वाला है। भारत द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग भारत की विदेश नीति की दृ ष्टि से एक सार्थक कदम है। भारत अब वह गुटनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है जिसकी विश्व महाशक्तियों के समक्ष कई मुद्दों पर मौन रहना एक विवशता थी।

विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय सतुलन और दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों, एशिया प्रशांत के देशों के सागरीय संप्रभुता से खिलवाड करने वाले चीन के व्यवहार को नियत्रित करने के लिए भारत द्वारा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। कोरोना महामारी के बीच पिछले माह ही भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर अपना सुरक्षा चक्र मजबूत किया। भारत के इस कदम ने चीन को काफी कुपित किया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने इस संबंध में कहा था कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम उब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव वाले सिद्धात का उल्लंघन करते है और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ है। मजे की बात यह है कि यह उस चीन की अपेक्षा हे जिसने दुनिया को कोरोना महामारी का दंश दिया।

इस तरह कोविड आपदा ने एक ऐसी बदलती विश्य व्यवस्था की दस्तक दे दी है. जहा आरोप-प्रत्यारोप के दौर के बीच पॉलिटिक्स ऑफ जेनरोसिटी यानी उदारता की राजनीति के जरिये वैश्विक छवि को निर्मित करने के प्रयास तो हो ही रहे है. साथ ही ताकत की राजनीति के जरिये कोरोना के बाद के काल में अपनी वैश्विक हैसियत को ऊचा करने का संघर्ष भी देखा जा रहा है। कोरोना आपदा की राजनीति ने अमेरिका की कमजोरी और चीन के गैर-जिम्मेदाराना नजरिये को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। इससे भारत जैसे उन देशों की वैश्विक भूमिका बढ़ गई है. जिनकी सॉफ्ट पावर के रूप में छवि भी बेहतर है और हाल के वर्षों में जिन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक, सैन्य और तकनीकी ताकत के रूप में देखा जाने लगा है।

वैश्विक राजनीति में भारत ने पहलकारी भूमिका की तलाश की है और इसी दिशा में हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में भारत सहित दुनिया के सात बडे देशों की बैठक भी हुई जिसमें कोविड-19 की उत्पत्ति के प्रति पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। हालाकि इसका मुख्य फोकस कोविड-19 को लेकर चीन की नकारात्मक भूमिका की आलोचना करना था। मगर भारत बखूबी जानता है कि कोविड के चलते अमेरिका कमजोर हुआ है और अमेरिका के कमजोर होने से महत्वाकांक्षी चीन की वर्चस्ववादी नीतियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। वहीं पिछले कुछ वर्षो से जिस प्रकार चीन भारत को उसकी सीमाओं व पडोस में घेरने की नीति अपनाता रहा है, ऐसे में चीन को मिलने वाली यह बढ़त भारत के सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए भारत ने वैश्विक गठजोड की नई राहें पकड़ी है।

भारत की परंपरागत बिग ब्रदर की छवि इसके लिए भारत अपनी छवि को सॉफ्ट पावर के रूप में और अधिक मजबूत आधार देने की कोशिश में जुटा है। जहां मेडिकल डिप्लोमेसी के जरिये भारत सार्क देशों को एक बार फिर एक मंच पर साथ लाने में कामयाब होता दिख रह है, वही पाकिस्तान के इस मंच पर भी गैरजिम्मेदाराना व्यवहार को निशाना बनाने के जरिये भारत ने दक्षिण एशियाई देशों को यह संदेश दे दिया कि भारत के लिए उसका पड़ोस प्रथम है। पठोसी देशों में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का बढ़ा उदाहरण नेपाल द्वारा 17 मई को भारत सरकार द्वारा दिए गए स्वास्थ्य सहायता के लिए धन्यवाद प्रेषण के रूप में देखा जा सकता है। यह भारत की परंपरागत बिग ब्रदर की छवि को बदलने का और पठोस प्रथम नीति को अधिक प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम अवसर है।

अफगानिस्तान को दी गई चिकित्सकीय सहायता भारत की प्रोएक्टिव विदेश नीति का ही प्रमाण है। इस महामारी के समय एक तरफ जहा तालिबान ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भारत पिछले चार दशक से अफगानिस्तान में नकारात्मक भूमिका निभाता आया है. तो वहीं अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को इसका जवाब देते हुए कहा है कि भारत वह देश है जिसने हमें सबसे ज्यादा दान दिया है और सबसे ज्यादा मदद की है। वास्तव में भारत ने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण कदमों से उन राष्ट्रों का भी विश्वास जीता है जो भारत का समय-समय पर अवसरवादी मानसिकता के कारण विरोध करते रहे हैं।

भारत ने विश्व समुदाय को चिकित्सकीय सहायता देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि वैश्विक स्वास्थ्य को वह वैश्विक मानवाधिकार के रूप में देखता है। भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलका को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 10 टन चिकित्सकीय सामग्री, नेपाल को 23 टन आवश्यक औषधि जिसमे हाइड्रॉक्सी क्लोरोवियन और पैरासिटामॉल आदि शामिल है व भूटान को व्यापक चिकित्सकीय आपूर्ति की खेप भेजी है। भारत ने बाग्लादेश को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की एक लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने व संयुक्त

अरब अमीरात को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के 50 लाख टैबलेट प्रदान किए है।

फिलहाल भारत कोरोना वायरस से प्रभावित करीब 55 देशों को सहायता और वाणिज्यिक आधार पर हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। भारत ने अमेरिका, सेशेल्स और मॉरीशस समेत म्यांमार, ब्राजील व इंडोनेशिया जैसे देशों को भी यह दवा भेजी है। इन सभी देशों ने भारत का आभार व्यक्त किया है। इस बीच बदलते दौर में दुनिया में आर्थिक संरक्षणवाद जिस तरह बढ़ रहा है. उस स्थिति में कोरोना के बाद के काल में विश्व में भारत को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में बड़े सरचनात्मक सुधार करने होंगे। आज के विश्व में सफल घरेलू नीति ही विदेश नीति को अधिक ठोस आधार दे सकती है। भारत सरकार को केवल विश्व की शक्ति राजनीति पर ही नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति की दिशा को स्वस्थ आधार देना ही होगा।

नए परिवर्तनों की आहट सुनाने वाला संकट: तमाम बदलते समीकरणों के बीच कोविठ-19 का असर भारत की विदेश नीति में कई रूपों में पढ़ सकता है। पहला, यदे भारत जैसे मिशन ने भारत के सबसे बढ़ी कूटनीतिक संपदा यानी भारतीय डायस्पोरा में भारत के प्रति निष्ठा का भाव मजबूत किया है। विश्व भर के विभिन्न देशों में फसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सात मई को शुरू किए गए यदे भारत मिशन के तहत अभी तक कुल 31 उठानों से 6,037 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। पहले चरण में कुल 14,800 भारतीयों को वापस लाने की योजना है। इसी प्रकार ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिये भारतीय नागरिकों को 'आइएनएस मगर' और जलश्व से मालदीव से स्वदेश लाया गया है।

दूसरा, चीन के प्रति विश्व में बढ़ते घृणा का भाव भारत के लिए बढ़ा अवसर है कि वह आर्थिक संबंधों में चीन का विकल्प बन सके। ऐसे में जब विश्व की अधिकांश कंपनियां चीन से बाहर निकल रही है तो भारत उनके लिए बेहतर गंतव्य स्थल के रूप में खुद को स्थापित करने में लगा है। भारत द्वारा रक्षा कंपनियों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है तो दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर दिया जा रहा फोकस भी इसी उद्देश्य से प्रेरित है। तीसरा, वर्तमान आपदा के दौरान भारत की विदेश नीति में एक और महत्वपूर्ण बात जो देखी गई है, वह है गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन का प्रभावी इस्तेमाल भारत की कूटनीतिक पहुंच और मानवतावादी प्रतिक्रिया को विश्व समुदाय के समक्ष रखने के लिए करना। भारतीय प्रधानमंत्री पर वर्ष 2016 और 2019 के 'नैम समिट' में भाग नहीं लेने और उसकी उपेक्षा के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब पीएम मोदी द्वारा महामारी से निपटने के लिए इसके वर्चुअल समिट को महत्व दिया गया है। भारत ने नेम के 59 देशों को चिकित्सकीय सेवाओं की आपूर्ति भी की है।

चौथा पढ़ाव चुनौतियों से जुड़ा है। मोदी सरकार के दौर में खाटी देशों सहित अन्य मुस्लिम देशो के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे थे, लेकिन हाल ही में दिल्ली में जमात प्रकरण और खादी देशों में सोशल मीडिया पर भारतीयों द्वारा मुस्लिम विरोधी बयानों ने इन रिश्तों में कुछ खटास ला दी है। दूसरी ओर चीन की नीतियां अधिक आक्रामक हो रही है। भारत का अमेरिका की तरफ दिखने वाला झुकाव भारत और चीन के बीच आमने-सामने के संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट की वजह से दुनियाभर में भारत संचालित विकास परियोजनाओं को यह महामारी प्रभावित कर सकती है। भारत की तृतीय विश्व के देशों में एक लीडर के रूप में इन प्रोजेक्ट्स का विशेष महत्व है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, श्रीलका में कटेनर टर्मिनल के निर्माण, बांग्लादेश और लैटिन अमेरिकी देशों में ऊर्जा परियोजनाए, विभिन्न देशों में मानवीय आधार पर बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के वित्त पोषण पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद भारत ने अपना मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं छोड़ा। यही इस बात की आंशका से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चीन कोरोना प्रभावित देशों को वित्तीय लालच देकर अपना वर्चस्व बढ़ाने का पुनः प्रयास करेगा।[5]

विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते, चीन क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए लगातार व्यापक व्यापार और आर्थिक एकीकरण पर बल देता रहा है। चीन ने पश्चिम के प्रभुत्व वाली बैट्टन वुड्स सिस्टम के विकल्प के तौर पर एक बार फिर से. एशियन इफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) जैसी नई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करने का प्रयास किया है। हालाकि व्यापार, आर्थिक और निवेश कानूनों के क्षेत्र में, देशों ने चीन की तरफ से पारदर्शिता के बारे में चिंताएं व्यक्त की है। चीन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक कानूनों की कमियो और खामियों का उपयोग कर अपनी सम्प्रभुता के अधिकारों को बढ़ावा देने के उपाय करना गुपचुप रूप से जारी रखे हुए है। अतीत की घटनाओं जैसे युवान के अवमूल्यन या चीन के बाजारों में बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों की शिथिल व्यवस्था का लक्ष्य अन्य देशों के समान हितों की कीमत पर उसके स्वयं के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना था।

अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के भविष्य के लिए चीन का दृष्टिकोण

अतीत में, चीन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से संबंधित अपने अनुभवों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था में भागीदारी से हिचकिचाता था। पूर्व-स्थापित, परम्परागत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी नियमों के लिए उसकी प्रतिक्रिया देश की सम्प्रभुता और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने जैसी चिंताओं से निर्देशित थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नित नए उभरते क्षेत्रों के साथ, चीन उसकी संकल्पना में भागीदारी के लिए बेताब है. ताकि वैश्विक कानूनी व्यवस्था में वह अपने विजन अहसास कराने में सहायक बन सके तथा अपने राष्ट्रीय और राजनीतिक हितों की रक्षा की गुंजाइश रख सके। नियमो पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका के तेजी से घटते सरोकारों के साथ वैश्विक नेतृत्व में शून्य उत्पन्न हो गया है। वैश्विक स्तर पर बेहद ताकतवर देश की अपनी उभरती भूमिका के मद्देनजर, चीन प्रभावी रूप से इस शून्य को भर सकता है और इस स्थिति का इस्तेमाल करते हुए वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के लिए अपने विजन के साथ तालमेल बैठाते हुए मौजूदा अतर्राष्ट्रीय कानूनों में बदलाव ला सकता है और नए कानूनों का निर्माण कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए ऐसे मार्ग के अनेक निहितार्थ है। उदाहरण के लिए, जहां एक ओर, वह पश्चिमी देशों के मानवाधिकारों की आढ में 'उदारवादी हस्तक्षेपवाद को हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर, वह घरेलू स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की अतर्राष्ट्रीय जाच समाप्त करा सकता है और रोहिंग्या शरणार्थियों जैसे संकट को बनाए रखने में मदद कर सकता है। भले ही दोषपूर्ण हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने नियमों और कानूनों से शासित होने वाला विश्व तैयार करने में मदद की है और वैश्विक व्यवस्था को अनुमान लगाए जा सकने लायक और कम अराजक बनाया है। राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय राजनीति की गतिशील प्रकृति तथा भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बीच यह देखना बाकी है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भविष्य की राह को चीन द्वारा ही आकार दिया जाएगा।[6]

वैश्विक स्तर पर ड्रैगन नहीं रह पाएगा विकास का अगुआ

साख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में 2020 की पहली तिमाही के दौरान 8.1 प्रतिशत सिकुड गई है। पिछले तीन दशकों में यह गिरावट पहली बार देखी गई है। कोरोना की मार के कारण एक तरफ चीन को अपने उत्पादन केंद्रों को बंद करना पठा तो दूसरी ओर दुनिया भर में इस महामारी के प्रकोप के चलते अन्य देशों में चीनी माल की खपत में भी भारी कमी के चलते यहां लॉकठाउन खुलने के बाद भी माग में उठाव दिखाई नहीं दे रहा है। चीनी माल के विदेशी ग्राहकों ने या तो अपने ऑर्डर को स्थगित कर दिया है अथवा निरस्त कर दिया है। नए और पिछले ऑर्डरों के भी भुगतान नहीं आ पा रहे है।

चीन से बढ़ती विमुखता: कोरोना महामारी के पहले से ही अमेरिका ने चीन के विरोध में व्यापार युद्ध छेड रखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयात शुल्क बढ़ाते हुए चीन से आने वाले आयातो पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। कोरोना महामारी के बाद अमेरिका ने चीन द्वारा इस वायरस को जानबूझकर फैलाने या उसके खतरों को दुनिया से छिपाने के बारे में कई आरोप भी लगाए है। अमेरिका ने इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी है। स्वाभाविक है कि इस सबके चलते चीन से अमेरिका को निर्यात प्रभावित होंगे। उधर इस संकट के समय दुनिया के अधिकाश देश आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अभी भी चीन पर निर्भर है। मेडिकल उपकरण, टेस्ट किट, मास्क, सैनिटाइजर समेत कई चीजों का आयात चीन से हो रहा है। लेकिन चीनी सामान की खराब क्वालिटी के चलते वे देश चीन से नाराज है और कई मामलों में खराब क्वालिटी के कारण चीन की खेपों को वापस भी किया जा चुका है।

आर्थिक संबंधों के बारे में पुनर्विचार: विभिन्न देश ऐसा मान रहे है कि कोरोना महामारी के पीछे चीन जिम्मेदार है। कई स्थानों पर तो चीन से हर्जाना वसूलने की भी बात चल रही है। गौरतलब है कि पिछले दो दशकों से अतरराष्ट्रीय बाजार में भी चीनी वस्तुओं की भरमार बढ़ती जा रही थी। यही नहीं चीन की सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां बढी मात्रा में अलग-अलग देशों में निवेश कर रही हैं। चीन के प्रति बढ़ते अविश्वास के चलते दुनिया के कई देश उसके साथ अपने आर्थिक संबंधों के बारे में पुनर्विचार करने लगे है। अमेरिका ने तो यहां तक कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण दुर्घटनावश हुआ है अथवा पठ्यत्रपूर्ण तरीके से, इसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर चीन को उसके परिणाम भुगतने होंगे।

दुनिया भर में कंपनियों की दुर्दशा और उनके शेयरों की कीमतें घटने के कारण चीन की सरकारी और निजी कंपनिया उनके अधिग्रहण की फिराक में है। उनके इस अनुचित प्रयास को रोकने के लिए कई देशों ने अपने विदेशी निवेश नियमों में बदलाव कर ऐसे निवेश को अमान्य किया है। हाल में भारत ने भी अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत चीन समेत उन सभी देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा, जिनकी सीमा भारत से जुडी हुई है।

भारत में परिवेश अनुकूल: आज दुनिया की लगभग एक हजार कंपनियां अपना उद्योग चीन से स्थानातरित कर भारत में स्थापित करने की इच्छुक है और केंद्र, राज्य सरकारों एवं अन्य आधिकारिक संस्थानों से वार्ता कर रही है। इनमें से 300 कंपनिया मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरणों और वस्त्रों के उत्पादन में संलग्न है। ये कंपनिया भारत को सर्वाधिक उपयुक्त गंतव्य मान रही है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया आज चीन पर अत्यधिक रूप से निर्भर है। इन कंपनियों को इस हेतु भारत में परिवेश अनुकूल दिख रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत इज ऑफ दूहग बिजनेस की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ता हुआ वैश्विक रैकिंग में 63वें स्थान पर पहुंच गया है।

कॉरपोरेट टैक्स दर न्यूनतम: यही नहीं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स मात्र 15 प्रतिशत कर दिया गया है। निवेश की दृष्टि से भारत के प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में यह कॉरपोरेट टैक्स दर न्यूनतम है। वर्तमान में कार्यरत कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की यह दर 22 प्रतिशत है, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में सबसे कम है। कुछ समय पहले कॉरपोरेट टैक्स दरों में इस बदलाव का लाभ यह होगा कि एक तरफ नए निवेशक यहा आने के लिए प्रोत्साहित होंगे और पहले से कार्यरत भारत से कही और जाने के लिए हतोत्साहित होंगे, क्योंकि इससे कम टैक्स वाला कोई देश नहीं है जहा वे जा सकें।

भारत की बढ़ती साख: पिछले कुछ समय से भारतीय नेतृत्व द्वारा दुनिया में भारत की साख बढ़ाने वाले कदमों से भारत का नाम काफी सम्मान से लिया जा रहा है। इस सकट के समय जब दुनिया के बढ़े और अमीर देश असहाय दिखाई दे रहे है. ऐसे में समझदारी, सख्ती और नागरिक सहयोग से जिस प्रकार भारत इस संकट से निपट रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील समेत कई देशों को दवाई उपलब्ध करा रहा है. इससे भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है। भारत की इसी बढ़ती साख का परिणाम है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार कई भारतीय दवाओं को बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड अनुमति मिली है।

सकट के समय में भी दवाओं की आपूर्ति द्वारा भारत ने दुनिया का दिल जीत लिया है। इस अनुकूल परिवेश का लाभ उठाते हुए भारत अपनी भूमि पर दवाइयो, मेडिकल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, केमिकल्स समेत अनेक उत्पादों के उत्पादन में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। माना जा सकता है कि चीनी वायरस भारत के लिए संकट और चुनोती कम् जबकि अवसर ज्यादा लेकर आया है। मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने शायद सही कहा है कि इस स्थिति को एमएसएमई के लिए प्रच्छन्न रूप से वरदान के रूप में देखा जाना चाहिए।

चीन आज निवेशकों की बेरुखी झेल रहा: पिछले करीब दो दशकों से वैश्विक बाजार में धूम मचाने वाला और वैश्विक निवेशकों का चहेता चीन आज न केवल निवेशकों की बेरुखी झेल रहा है, बल्कि पहले से स्थापित विदेशी कंपनियां चीन से कूच की तैयारी कर रही है। जापान सरकार ने चीन से कूच करने वाली अपनी कंपनियों को दो अरब डॉलर की मदद देने का फैसला लिया है, ताकि वे आसानी से इस काम को अंजाम दे सकें। उधर पिछले लगभग एक दशक में अपने विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक शक्ति के बलबूते चीन की सरकार और कंपनियों ने दुनिया भर में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। विश्व भर में चीन की सरकारी और गैर सरकारी कपनियों ने बड़ी संख्या में कपनियों का अधिग्रहण ही नहीं किया, बल्कि अफ्रीका समेत कई मुल्कों में उन्होंने बड़ी मात्रा में भूमि भी खरीद ली।

वन बेल्ट वन रोड परियोजना: इसके अलावा पिछले कुछ वर्षो में वन बेल्ट वन रोड परियोजना के अंतर्गत चीन की सरकार और सरकारी एवं निजी कंपनियों ने भारी मात्रा में दुनिया के 65 से ज्यादा देशों के संरचनात्मक ढांचे में निवेश करना शुरू कर दिया। यह कह कर कि इस परियोजना से न केवल उनके संरचनात्मक ढांचे का विकास होगा, बल्कि वे दुनिया के सबसे बड़े सडक-रेल-जलमार्ग का हिस्सा भी बनेंगे, लेकिन इस तरह उन्होंने दुनिया के मुल्को को सिर्फ अपने कर्ज के जाल में फंसाया। उन्होंने ऐसी बड़ी परियोजनाओं को शुरू किया जिसकी व्यावसायिक आवश्यकता ही नहीं थी, पर उस पर किया गया खर्च उन देशों पर कर्ज को बढ़ाता चला गया। चीन की कंपनियों को ठेके मिले और चीनी कार्मिकों को काम मिला, लेकिन उन मुल्कों को मिला तो केवल कर्ज का बोझ। ऐसा बोझ जो वे उतार ही न पाएं।

सामरिक दृष्टि से कमजोर: कई देशों में चीन का राजनीतिक दखल भी बढ़ चुका है जिससे उन देशों की जनता त्रस्त है। यही नहीं चीन की कई कंपनिया दुनिया भर में चल रहे व्यवसायों का अधिग्रहण करने में संलग्न है। भारत में पेटीएम समेत कई पेमेंट कंपनियों और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों का अधिग्रहण चीन ने किया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत प्रारंभ किए गए स्टार्टअप व्यवसायों को भी चीनी निवेशकों की फडिंग के माध्यम से कब्जाया जा रहा है। चीनी कपनियों, चीनी वस्तुओं और चीन द्वारा प्रस्तावित बेल्ट रोड के प्रति दुनिया का पहले से रुख बदल ही रहा था। दुनिया को समझ आ रहा था कि चीन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तहस-नहस करने, उन्हें कर्ज के बोझ में दबाने, रोजगार को नष्ट करने, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के रास्ते डाटा (आकटो) पर कब्जा जमाकर सामरिक दृष्टि से उन्हें कमजोर कर रहा है। लेकिन पिछले लगभग दो माह में परिस्थितियां चीन के और अधिक खिलाफ हो चुकी है। चीनी वायरस के कहर के कारण दुनिया भर में एक ओर विनिर्माण प्रभावित हुआ है तो दूसरी ओर विभिन्न देशो की आपातकालीन परिस्थितियों के चलते चीन से मास्क, पीपीई किट्स और कोरोना टेस्ट किट्स की माग बढ़ गई है। इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने न केवल कीमतें बढ़ा दी है, बल्कि घटिया सामान भी निर्यात करना शुरू कर दिया। ऐसे में पहले से ही चीन से शुरू हुए वायरस से त्रस्त देशों का चीन के प्रति गुस्सा और अधिक बढ़ गया और उन्होंने चीन से आए घटिया सामान को लौटा दिया है। कई देशों ने तो चीन को इन वस्तुओं की कीमत का भुगतान भी नहीं करने की बात कही है। आज भारत समेत दुनिया के उन तमाम देशों के नागरिक भी जागरूक हो रहे हैं और चीन से आयातित वस्तुओं के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है।

भारत के लिए यह अनुकूल दशा कही जा सकती है। दुनिया भर में चीन के प्रति गुस्से और उसके कुत्सित प्रयासों के खिलाफ बढ़ती जागृति के चलते भविष्य में चीन के दूसरे मुल्को के साथ आर्थिक संबंध पूर्व जैसे नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि चीन ने पिछले दो दशकों में भूमंडलीकरण का जो लाभ उठाया है उसके आगे का रास्ता सुगम नहीं दिख रहा है।[7]

विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा रहा चीन

एशिया का अकेला नेतृत्व करने की इच्छा रखने वाला चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के बढ़ते कद से परेशान है। वर्तमान में चीन, भारत को एक प्रतिद्वंद्वी की तरह देख रहा है। चूंकि भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में जहाँ एक तरफ भारत सम्पूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हुआ है तो दूसरी और चीन अपनी नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अलग थलग नजर आ रहा है।

चीन की नीतियों के संदर्भ में देखे तो चीन ने हमेशा आक्रामक विस्तारवादी विदेश नीति को केंद्र में रखा है। यही कारण है कि 20वीं सदी से 21वी सदी तक चीन अपने भूभाग को बढ़ाने हेतु अतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जिया उठाते भी बाज नहीं आता है। 1959 में चीन की जमीन के प्रति भूख के कारण तिब्बत जैसे शांत प्रिय राष्ट्र को अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोना पड़ा और वहाँ के नागरिको को चीन के अत्याचार के कारण दूसरे देशों में शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा। चीन एक शातिर देश है निश्चित ही तिब्बत पर कब्जा करने का मंशा भारत को ही केन्द्रित करके की होगी क्योंकि तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात एक तो भारतीय सीमा के निकट पहुंचने में सफलता प्राप्त मिली और पाकिस्तान जैसे सदाबहार मित्र का पठोसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के माध्यम से बना। अर्थात पीओके से ही चीन की सीमा पाकिस्तान से लगती है जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो दूसरी ओर चीन ने जल नियत्रण करने की शक्ति हासिल करने में सफलता प्राप्त की।

दरअसल जल नियंत्रण से तात्पर्य है कि भारत में बहने वाली तीन सदावाहिनी नदियों (ब्रह्मपुत्र, सिधु, सतलुज) का उद्गम स्थल तिब्बत में है। ज्ञात है कि चीन ने बह्मपुत्र नदी पर बांध बनाया है। उसके माध्यम से गर्मियों में पानी की कमी के समय भारत का पानी रोकने में सक्षम है जिससे नार्थ ईस्ट इलाके को सूखे का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर वर्षा के दिनों में अत्यधिक जल की स्थिति में बाघ का फाटक खोलने पर नार्थ ईस्ट इलाका जलमग्न हो सकता है। सतलुज नदी के संदर्भ में देखें तो इसका उद्गम स्थल भी तिब्बत (राक्षस ताल) ही है। ऐसे में सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बाँध पर बनी जल विद्युत स्टेशन, करचम वांगटु हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लाट और नाथपाझाकडी जल विद्युत परियोजना को प्रभावित करने की भी शक्ति हासिल है।

ज्ञातव्य है कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से काफी लंबे समय से पीडित है। इसी

कारण पाकिस्तान पर दबाव बनाने हेतु सिर्फ कहा ही गया था कि हो सकता है सिंधु नदी के जल की समीक्षा कर भारत अपने हिस्से के जल का इस्तेमाल करे। फिर क्या था पाकिस्तान के सदाबहार मित्र चीन ने तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का पानी रोक कर पाकिस्तान के साथ मित्रता को बखूबी निभाया। यहाँ तक कि चीन ने आतंकवाद के प्रति दोहरा रवैया अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित होने से भी बचाया। जबकि चीन स्वयं भी उइघुर प्रांत में आतकवाद से पीड़ित है। चीन ने पाकिस्तान के माध्यम से भारत की सुरक्षा के समक्ष काफी चुनौतियां खड़ी की बावजूद भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के मसले पर अलग थलग करने में कामयाब रहा। यही कारण है कि विश्व के कई देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, अफगानिस्तान, यूरोपीय यूनियन के देश, आसियान देश इत्यादि भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हाल में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हिजबुल के चीफ सैयद सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। इसके लिए कश्मीर में हो रहीं आतंकवादी गतिविधियों को आधार बनाया गया है। इस पर चीन ने कहा था कि अमेरिका को दूसरे देशों की सम्प्रभुता का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन के मुद्दे पर आतकवाद के प्रति चीन के दोहरे रवैये से संपूर्ण विश्व परिचित हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि एशिया में भारत को प्रतिद्वद्वी मानकर चीन भारत की विकास यात्रा को पाकिस्तान के माध्यम से बाधित करता है। अर्थात सारा ध्यान पाकिस्तान और कश्मीर पर रहे और चीन अपने विकास कार्यो को सुचारू रूप से करता रहे। यहाँ तक कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के दावे का भी विरोध करता है।

दक्षिण चीन सागर के सदर्भ में चीन की नीति से संपूर्ण विश्व परिचित है। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत दक्षिण चीन सागर पर वह अपने एकाधिकार का दावा करता है लेकिन दक्षिण चीन सागर किसी एक देश की धरोहर न होकर एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक मार्ग है। साथ ही दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती देश इस पर प्राकृतिक तेल, गैस, ऊर्जा, मत्स्य सुरक्षा इत्यादि हेतु निर्भर है। ऐसे में चीन द्वारा विवादित द्वीपों पर कब्जा और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के माध्यम से अपने क्षेत्र में वृद्धि करने की नीति और कृत्रिम द्वीपों पर नौसैनिक अड्डा बनाए जाने के कारण दक्षिण चीन सागर के तटीय देश (वियतनाम, फिलीपीस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि) चीन से नाराज है। इसलिए ये तटवर्ती देश चीन से दूरी बना रहे है और भारत के साथ निकट सानिध्य महसूस करते है। ऐसे में चीन की विस्तारवादी मानसिकता के कारण तटवर्ती देश चीन के विरुद्ध लामबंद हो रहे है। इस प्रकार दक्षिण चीन सागर में चीनी वर्चस्व चीन को न केवल महाशक्तियों से अपितु उसके पड़ोसियों से भी दूर कर रहा है।

भारत, तिब्बत और भूटान की सीमा पर देखे तो चीन द्वारा भूटान के भूभाग को हडपने के नियत के कारण सीमा पर तनाव जारी है। दरअसल तिब्बत की तरह भूटान को छोटा और कमजोर राष्ट्र समझकर चीन की मंशा उचित प्रतीत नहीं होती है। ढोकलाम के संदर्भ में विवादास्पद नक्शे को जारी कर चीन ने उस भूभाग को अपना बताकर मशा जाहिर कर दी है। चूंकि भूटान सरकार का भारत सरकार के साथ सुरक्षा समझौता है। ऐसे में भूटान की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार के पास है। इसलिए भूटान के अनुरोध पर भारतीय सैनिकों ने डोकलाम में चीन के सडक निर्माण कार्य को रोक दिया। तब से भारत और चीन के मध्य तनाव जारी है और बीन ने तो भारत को युद्ध की धमकी तक दे डाली।

वर्तमान में जिस प्रकार चीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार कर रहा है उससे निश्चित ही काफी देश उसके विरोधी ही नजर आएंगे क्योंकि चीन अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति हेतु किसी भी देश की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो चीन की कंपनियों ने श्रीलंका में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में भारी भरकम निवेश किया है और श्रीलंका को कर्ज देने वाली चीनी कंपनियों द्वारा काफी ऊँचे दर पर व्याज वसूलने के कारण श्रीलंका की वित्तीय स्थिति को काफी नुकसान हो रहा है। श्रीलंका द्वारा ऋण वापस नहीं लौटाए जाने की स्थिति में चीनी कंपनिया मालिकाना हक माग रही है। दरअसल चीन ने आधारभूत संरचना हेतु जिन परियोजनाओं में श्रीलंका में निवेश किया है वह चीन की महात्वाकांक्षी परियोजना वन वेल्ट वन रोड का हिस्सा है। ऐसे में स्पष्ट है कि चीन छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारी भरकम निवेश कर उनकी अर्थव्यवस्था को कर्ज के जाल में फसा रहा है ताकि 21वी सदी में भी अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखे।

श्रीलंका ही नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी चीन अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है और चीन का सदाबहार मित्र पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। कुछ अफ्रीकी देशो में भी चीन की यही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, इसलिए कई अफ्रीकी देश भी चीन की महात्वाकांक्षी परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में चीन की छवि एक साम्राज्यवादी देश की तरह उभर रही है जो अतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के लिए घातक सिद्ध होगी और चीन अलग थलग पड जाएगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष है। पडोसियों (चीन, पाकिस्तान) द्वारा भारत की विकास यात्रा में रोढे अटकाने के बावजूद भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने की दिशा में अग्रसर है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक रिसर्च पेपर के अनुसार भारत 2024 में अतर्राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर विश्व के समक्ष उपस्थित होगा, खासतौर से आर्थिक शक्ति के रूप में।[8]

इस प्रकार आंकड़ों की बात करें तो चीन की जीडीपी में वर्ष 1978 से 2016 के बीच 3,230 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया और 38.5 करोड़ लोग मध्य वर्ग में शामिल हुए। चीन का विदेशी व्यापार 17,500 फीसदी बढ़ा और 2015 तक चीन (बेपदं) विदेशी व्यापार में दुनिया का अगुवा बनकर सामने आया। आज के समय में चीन दुनिया की सबसे बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था है। डांग श्याओपिंग अक्सर टू-कैट थिअरी का उल्लेख किया करते थे कि जब तक बिल्ली चूहे को पकडती है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सफेद है या काली। इसी का परिणाम था कि 1979 से 2010 तक, चीन की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 991 प्रतिशत थी, जो 1984 में 15.2 प्रतिशत के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इससे एक समय में वैश्विक व्यापार से 100 कोस दूर रहने वाला चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था। विश्व के बड़े से बड़े देश चीन पर इस कदर से निर्भर हो चुके थे कि चीन के एक झटके से उनकी अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता था। चीन (बेपदं) ने मैन्युफैक्चरिंग में 110 वर्षो से चले आ रहे अमेरिका के नेतृत्व को पछाड़ दिया है। दुनिया के कुल कच्चे स्टील के उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा चीन का है। परंतु इस वर्ष जनवरी 2020 से ही फैले कोरोना वायरस ने विश्व के देशों को यह याद दिलाया है कि चीन जैसे देश पर अत्यधिक निर्भरता किस तरह उनके अर्थव्यवस्था को नीचे पटक सकती है। चीन के वुहान से कोरोना फैलने के कारण सभी देश चीन के खिलाफ हो चुके है। वर्तमान आर्थिक स्थिति को 1939 के महामंदी के बाद से सबसे खराब दौर करार दिया गया है। IMF ने 2020 में वैश्विक वृद्धि दर को 3 प्रतिशत घटा दिया है। महामारी संकट के कारण 2020 के वैश्विक व्यापार में 13 प्रतिशत से 32 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है और और यह गिरावट 2008 के वित्तीय संकट से अधिक हो सकती है।[9]

आज समस्त विश्व चीनी वायरस से युद्धरत है परंतु चीन अपने सामरिक हित साधने में लगा है। आर्थिक मोर्चे से लेकर राजनीतिक मोर्चे और सैन्य मोर्चे से लेकर कूटनीति तक चीन की सक्रियता पूर्ववत है। संयुक्त राष्ट्र पर चीनी वायरस के मुद्दे पर बहस से लेकर अपने औद्योगिक इकाइयों को सुचारु रूप से चलाने तक चीनी उद्यमिता और प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। चीन ने विश्व को चीनी वायरस कोरोना की रोकथाम के लिए औषधीय उपकरण भी उपलब्ध कराने आरंभ कर दिये हैं। चीन अपनी सामरिक शक्ति के सहारे चीनी वायरस के मुद्दे को विश्व में अपने विरुद्ध नहीं जाने देने के लिए प्रयासरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी अपने पाले में रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के अतिरिक्त कोई भी चीन की चालों पर नहीं बोल रहा। अकेले ट्रम्प ही है जो कोरोना को चीनी वायरस कहकर बुलाते हैं। यकीनन चीन की आर्थिक शक्ति से सभी सहमे हुये है। भारत में भी एक वर्ग ऐसा है जो चीनी टुकडों पर पलता है। उसे कोरोना को चीनी वायरस बोले जाने पर आपत्ति है। कई लुटियन पत्रकार तो चीनी वायरस बोले जाने पर बौखलाए नजर आए। कोरोना महामारी के संकटकाल का लाभ भी चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य शक्ति और उपस्थिति से ले रहा है। चीनी तटरक्षकों ने अप्रैल के पहले सप्ताह में वियतनाम के मछुआरों के पोत को दक्षिण चीन सागर के पार्शल द्वीप के पास टक्कर मारकर डुबो दिया तो दूसरे सप्ताह में फिलीपीस को अपना शिकार बनाया। एशियान के सभी 10 देश चीन के किसी भी कृत्य को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को साधने वाला अमेरिका अभी चीनी वायरस के कारण घरेलू संकट से जूझ रहा है। ऐसे में चीन किसी भी वैश्विक नियम-कानून को मानने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में चल रहा हिंसक घटनाक्रम चीन की मोन सहमति के बिना कदापि संभव नहीं है क्योंकि कतर की अमेरिकी तालीबान शाति वार्ता में चीन भी एक प्रतिनिधि था। चीन अफगानिस्तान में कभी भी भारतीय उपस्थिति को नहीं चाहता जिसके अनेक सामरिक और भू-रणनीतिक कारण है। एशियान देशों से भारत के प्रगाढ संबंध भी चीन की आख में किरकिरी बने हुए है। भारत के जापान और दक्षिण कोरिया से भी अच्छे सामरिक और व्यावसायिक संबंध है। इन देशों से होने वाले समुद्री व्यापार को दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन द्वारा बाधित होने का संकट चिंता का विषय है। दक्षिण चीन सागर से लगने वाली सभी समुद्री सीमाओं का अनाधिकृत उल्लघन चीन की रणनीति का हिस्सा है।[10]

REFERENCES

1. चीन की राजनीति का नया रूप, दैनिक जागरण, 29 अप्रैल, 2012

2. दुनिया का 'आर्थिक चमत्कार कैसे बन गया कभी गरीब रहा चीन, बीबीसी न्यूज 5 अक्टूबर, 2019

3. कुमारा, प्रदीप आलेख "कोरोना के बीच भी विश्व वर्चस्व की होड, अमर उजाला, 4 अप्रैल, 2020

4. दुबे, नीरज कुमार आलेख "सिर्फ अपनी बादशाहत के लिए चीन ने पूरी दुनिया को मौत के मुँह में झोक दिया है" प्रभा साक्षी समाचारपत्र, 30 मार्च, 2020

5. कोरोना काल में विदेश नीति से बड़ा संदेश, चीन का साथ छोड़ भारत ने थामा अमेरिका का हाथ, जागरण, 20 मई, 2020

6. टिरके, आरसरी आलेख क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति चीन का नजरिया" ऑब्र्जवेशन रिसर्च फाऊडेशन, 5 जून, 2018

7. महाजन, अश्विनी आलेख "वैश्विक स्तर पर ड्रैगन नहीं रह पाएगा विकास का अगुआ, भारत के लिए अनुकूल बनता परिदृश्य, जागरण, 5 मई, 2020

8. वर्मा, अनीता आलेख विस्तारवादी नीति के तहत पडोसियों को कर्ज के जाल में फंसा रहा चीन" प्रभा साक्षी समाचारपत्र, 15 जुलाई, 2020

9. चीन के बिना, चीन के साथ और अब फिर चीन मुक्त दुनिया जाने चीनी चक्र में उलझे देशों की कहानी, नवजागरण टाइम्स, 25 मई, 2020

10. सिह आदित्य प्रताप आलेख चीनी चाल, दुनिया बेहाल अप्रैल, 2020